SHRI RAMA RAO: Well, Sir, I beg leave to withdraw it.

The Resolution* was, by leave, withdrawn.

SHRI M. MANJURAN (Travancore-Cochin): But, Sir, should he not have the leave of the House for withdrawing his Resolution?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are too late. He has got the leave of the House.

RESOLUTION *RE* BASIC EDUCATION

SHRI D. NARAYAN (Bombay):

श्री डी० नारायण (बम्बई): Sir, I beg to move the following Resolution:

"This Council is of opinion that Government should take early steps—

(a) towards the implementation of the provisions of article 45 of the Constitution of India; and

(b) to declare basic education as the pattern of national system of education to be hereafter established in India.

This Council is further of opinion that Government should immediately establish a basic education section in the appropriate Ministry for co-ordinating and circulating useful information to the States with regard to basic education and for serving as a liaison with training institutions and educational departments."

श्रीमन्, भाषा शास्त्रियों के शास्त्रार्थ के बाद मैं अपना यह सीधा सादा प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं। यह प्रस्ताव सीधा सादा होते हुए भी, मैं कहना चाहता हूं कि देश की असंख्य जनता की आवाज इसके द्वारा मैं आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं। पांच लाख देहातों में जो मूक जनता आज करोड़ों की संख्या में रहती है उनकी यह आवाज है, उनकी यह आकांक्षा है, जो कि इस प्रस्ताव में रखी है। आप जानते हैं कि यह देश ऐसा देश है कि जहां की बहुसंख्यक जनता निरक्षर है, न पढ़ना जानती है और, न लिखना। मैं अभी तक सुन रहा था साहित्य की बातें, और उन देहातियों के बारे में सोच रहा था कि क्या वे बिचारे इन बातों को समझ सकते हैं जिनकी चर्चा यहां हो रही थी। आज इस देश में सिर्फ १७ फीसदी ऐसे आदमी हैं, जो मामूली पढ़ना लिखना जानते हैं और सैकड़ा में ८३ ऐसे हैं जिनके लिये काला अक्षर भैंस बराबर है। ऐसी हालत में आप जानते हैं कि उनकी आकांक्षा क्या हो सकती है।

इस मुल्क के दो दुश्मन है, एक गरीबी और दूसरा अज्ञान। आज जो सभ्य देश कहलाते है—और भारतवर्ष को भी अभिमान है सभ्य कहलाने का—उन देशों में कहीं पर भी हिन्दुस्तान के बराबर निरक्षर लोग आप को दिखाई नहीं देंगे। किसी भी सभ्य देश को देखियेगा, वहां साक्षर लोगों की संख्या १०० में से ९० होगी, ९८ होगी, और कहीं कहीं तो पूरे सौ प्रतिशत होगी। रशिया (Russia) में जहां १९१७ से पहले हिन्दुस्तान से भी गिरी हालत थी, वहां अब निरक्षरता बिलकुल नहीं रही और पढ़े लिखों की, साक्षरों की, संख्या सेंट पर सेंट (cent per cent.) हो गई है। अमेरिका एक देश है, जिसका बहुत कुछ अनुकरण इस देश में होने लगा है, हालांकि यह बड़े दुःख की बात है, वहां भी सैकड़ा पीछे ९८ लोग साक्षर हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए हमारे कंस्टीट्यूशन (Constitution) के बनाने वालों ने यह आदेश हम को दिया कि इस देश में सर्वत्र फ्री और कम्पलसरी प्राथमिक शिक्षा दस वर्ष में पूरी

*For text of Resolution, *see* column No. 628 *supra*.

की जाय । कंस्टीट्यूशन की धारा ४५ इस प्रकार है :

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

मैं पूछता हूं कि आखिर यह हो भी रहा है ? तीन वर्ष कंस्टीट्यूशन को पैदा हुए हो गये, इस दिशा में कहां तक हमने कदम बढ़ाया है ? चालीस वर्ष पहले सन् १९१२ में उस वक्त की इम्पीरियल काऊंसिल (Imperial Council) में स्वर्गीय देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि इस देश में फ्री और कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन (free and compulsory primary education) हो। उस दिन से आज तक हम बहुत कुछ आगे नहीं बढ़े हैं। हां, कुछ प्रयत्न अब आजादी के बाद होना शुरू हुआ है । परन्तु वह बहुत ही कम है । सोचिये, कि इस आदेश के अनुसार प्राथमिक शिक्षा छः से चौदह वर्ष तक के लड़के लड़कियों के लिये फ्री और कम्पलसरी होने को है। इस उम्र के लड़के लड़कियों की इस देश में तादाद पांच सवा पांच करोड़ है । और आज जो शिक्षा का प्रबन्ध है, उसके अन्तर्गत छः से ग्यारह तक की उम्र की ही चर्चा की जा रही है। छः से ११ तक के लड़के लड़कियों की संख्या इस मुल्क में ४ करोड़ ४० लाख २९ हजार के क़रीब है, और आज की पाठशालाओं में इन ४ करोड़ ४० लाख २९ हजार में से १ करोड़ ४१ लाख १३ हजार लड़के लड़कियां शिक्षा पा रहे हैं। या यूं कहिये कि सिर्फ इतने ही लड़के लड़कियों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध है ।

यह कुल ४० टका तादाद है, यानी ४० परसेंट ६ से ११ वर्ष की उम्र के लड़के लड़की आज शिक्षा पा रहे हैं और ६ से ११ वर्ष के ६० फीसदी लड़के लड़की अभी शिक्षा से वंचित हैं। यह जो ४० टका हैं ये भी इस देश में एक से बटे हुए नहीं हैं, कहीं ज्यादा हैं और कहीं कम हैं। ट्रावनकोर-कोचीन में ९८.८ परसेंट, बम्बई में ६४ परसेंट, मैसूर में ५७ परसेंट, मद्रास में ५२.७ परसेंट, आसाम में ४९.७ परसेंट, सौराष्ट्र में ४२.४ परसेंट, वेस्ट बंगाल में ४०.५ परसेंट, उत्तर प्रदेश में ३४ परसेंट, बिहार में २९.३ परसेंट, हैदराबाद में २६.२ परसेंट, पंजाब में २४.४ परसेंट, उड़ीसा में २४ परसेंट, मध्य भारत में २०.१ परसेंट, मध्य प्रदेश में १९.९ परसेंट, पेप्सू में १०.६ परसेंट और राजस्थान में, जहां कि भाग्यवान अधिक बसते हैं, १०.६ परसेंट है ।

THE DEPUTY MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND SCIENTIFIC RESEARCH (SHRI K. D. MALAVIYA):

प्राकृतिक साधन व वैज्ञानिक गवषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : भगवान बसते हैं ?

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : मैंने भाग्यवान कहा ।

SHRI K. D. MALAVIYA:

श्री के० डी० मालवीय : मैंने समझा कि आपने भगवान कहा ।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : आपको कम सुनाई दिया ।

मेरा कहना है कि सरकार को इस प्रश्न की ओर जितना ध्यान देना चाहिये उतना वह ध्यान नहीं दे रही है। सरकार आज प्राथमिक शिक्षा के लिये जो खर्च कर रही है वह इतना कम है कि यह कहा जा सकता है कि जनता की इस आकांक्षा और मांग की ओर सरकार

[Shri D. Narayan.]

उपेक्षा की ही दृष्टि से देख रही है । राज्य सरकारों और सेन्ट्रल (Central) सरकार का सालाना खर्चा ८०० करोड़ रुपये के आसपास है, जिसमें शिक्षा के ऊपर सिर्फ ७१ करोड़ रुपये खर्च होते हैं, इसमें हाई स्कूल (High School) शिक्षा भी शामिल है, यूनिवर्सिटी (University) शिक्षा भी शामिल है और अगर इन दोनों का खर्चा निकाल दिया जाय, तो यह कहा गया है कि सैकड़ा पीछे ३४.२ प्राइमरी शिक्षा में खर्च होता है. यानी बड़ी मुश्किल से ७१ करोड़ में से २४ करोड़ रुपया सारे देश में प्राइमरी शिक्षा के ऊपर आज खर्च हो रहा है ।

मैंने आपसे कहा कि ६ से ११ वर्ष की उम्र के १ करोड़ ४१ लाख लड़के लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध है । आज कुछ राज्यों में कहीं कहीं कम्पलसरी फ्री एजूकेशन (compulsory free education) जारी हो गई है और जहां तक मुझे पता है, करीब १ करोड़ लड़के लड़कियां इस कम्पलसरी योजना के मातहत आज पढ़ रहे हैं । परन्तु यह कम्पलशन (compulsion) चलता नहीं है । क्यों ? गरीबी के कारण । गरीबी के कारण बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते और उन पर कानून का उपयोग भी कामयाब नहीं होता । मुझे पता है कि बम्बई राज्य में कई जगह पर फ्री और कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन योजना शुरू की गई है । अटेंडेंट आफिसर्स (attendant officers) भी हैं, लेकिन अटेंडेंट आफिसर्स करें क्या ? गरीबी की वजह से लड़के स्कूलों में आते नहीं हैं और आप उन पर जुर्माना करें तो फिर जुर्माना वसूल करें कहां से । तो साथ में यह भी सोचना चाहिये कि फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन तभी हो सकती है जब कि देहातों की माली हालत भी कुछ सुधरे या बच्चों की पढ़ाई के समय में उनके खाने पीने की कुछ व्यवस्था की जाय ।

आज प्राथमिक शिक्षा पर फी लड़के के पीछे १६ रुपये खर्च हो रहे हैं और हाई स्कूल के एक लड़के के ऊपर इससे तीन गुना रुपया खर्च हो रहा है और यूनिवर्सिटी के एक लड़के के ऊपर २० गुना खर्च हो रहा है और यह २० गुना और ३ गुना खर्चा सरकार कर रही है । वह यह नहीं सोचती कि आज लाखों करोड़ों लड़के निरक्षर हैं और पढ़ने पढ़ाने की इच्छा होते हुए भी आज गरीबी के कारण वे पढ़ नहीं सकते और कुछ प्रबन्ध भी कर नहीं सकते। अच्छा तो यह होता कि हमारी सरकार पहले आम जनता के इन गरीब लड़कों का खयाल करती और उसके बाद यूनिवर्सिटी शिक्षा का खयाल करती । पूज्य महात्मा गांधी ने यह राय दी थी कि सर्वत्र कम्पलसरी फ्री एजूकेशन किया जाय और यूनिवर्सिटी एजूकेशन उन लड़कों के लिये छोड़ दी जाय जो कि खुद अपना खर्च कर सकें । सरकार को आम जनता का पैसा कुछ मुट्ठी भर लोगों की शिक्षा के लिये नहीं खर्च करना चाहिये, जैसा कि आज किया जा रहा है ।

कुछ दिन हुए सरकार ने एक कमेटी कायम की थी, दी कमेटी आन वेज एण्ड मीन्स ऑफ फाइनेंन्सिंग एजूकेशनल डेवलपमेंट (The Committee on Ways and Means of Financing Educational Development). इस कमेटी की रिपोर्ट (report) निकली है । उस रिपोर्ट के अनुसार यदि इन ६ से १४ वर्ष तक के लड़के लड़कियों को शतप्रतिशत प्राथमिक शिक्षा देनी है और इनमें से २० टकों को यानी २० फीसदी को हाई स्कूल की शिक्षा देनी है और १० फीसदी को यूनिवर्सिटी शिक्षा देनी है तो ४०० करोड़ रुपया सालाना चाहिये ।

कहां ७१ करोड़ रुपया और कहा ४०० करोड रुपया ? स्वप्न की सी बाते है। पचवर्षीय योजना भी आपने देखी होगी जिसमे कि इस ४०० करोड़ का जिक्र है। पचवर्षीय योजना को बनाने वालो ने पाच वर्ष में १५१ करोड रुपया शिक्षा के लिये निश्चित किया है, यानी शिक्षा के लिये ३० करोड रुपया सालाना दिया जायेगा। सोचिये कि जहा करोडो लडके और लड़किया स्कूलो में जाने के योग्य है उस मुल्क में ३० करोड रुपये के देने के बाद भी आप कैसे आशा कर सकते है कि सविधान के आदेश के अनुसार दस वर्ष मे पाच करोड़ बच्चे हमारे साक्षर हो सकेगे और स्कूल मे पहुंच जायेगे। साथ मे यह प्लान (Plan) बनाने वाले महाशय यह भी कहते है :

"The emphasis on the primary education needs to be very considerably increased during the Plan period"

How can it be increased with Rs 30 crores per year ?

बाद मे फिर कहते है :

"The provision of free and compulsory education is the first necessary step towards establishing equality of opportunity of every citizen."

कहां है इक्वालिटी आफ अपारचुनिटी (equality of opportunity)? जरा सोचिये, प्राथमिक शिक्षा के लिये एक लड़के के ऊपर क्या खर्च करते है और यही सरकार यूनिवर्सिटी शिक्षा के ऊपर क्या खर्च कर रही है। इन तमाम बातो को सोच कर ही महात्मा गांधी ने यह कहा था :

"We shall realise universal education only by teaching the children a useful vocation and utilising it as a means for cultivating their mental, physical and spiritual faculties. The whole education should be imparted through some handicraft or industry."

बुनियादी तालीम का जन्म कैसे हुआ इसका पता आपको इन बातो से चल सकता है। हिन्दुस्तान के तमाम देहातों को घूम कर राष्ट्रपिता ने यह देखा कि हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता साक्षर नही हो सकती, पढ लिख नही सकती, जब तक कि प्राथमिक शिक्षा में ही उसे कुछ जीवन का सहारा न मिले, जब तक कि ऐसा न हो कि उद्योग के जरिये ही पढाई हो और इसीलिये उन्होने देश के सामने बेसिक एजुकेशन (basic education) की, बुनियादी तालीम की कल्पना रखी। सौभाग्य से आज वह कल्पना सारे देश मे ही नहीं, सारी दुनिया में मान्य हो गई है। शिक्षा शास्त्रियों ने भी उसे मान लिया है। जितनी कांफरेंसेज (Conferences) इस देश में होती है, चाहे जनता की ओर से होती हों या सरकार की ओर से होती हों, सभी में इस बेसिक योजना को स्वीकार कर लिया जाता है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा तथा दूसरी उच्चशिक्षा के सम्बन्ध मे एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन (Central Advisory Board of Education) कायम कर रखा है। इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने भी बेसिक एजूकेशन की पद्धति को स्वीकृति दे दी है और यह भी कहा है कि सारे देश मे प्राथमिक शिक्षा नई तालीम की पद्धति से दी जाय। पचवर्षीय योजना के बनाने वालों ने तो यहा तक कहा है कि आगामी प्राथमिक पाठशालाये सब बेसिक ढग की ही हो और जो प्राथमिक पाठशालाये अभी है वे भी धीरे धीरे बेसिक बना दी जाय। ये तमाम बाते होनी है, लेकिन कब ? जब खर्च को पैसा होगा। राज्य सरकारे इतना बोझा उठा नही सकती है, इसलिये सेंट्रल गवर्नमेंट (Central Government) को मदद करनी होगी।

[Shri K. D. Malaviya.]

श्री के० डी० मालवीय : कैसे करें यह बताइये ।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण: आज की शिक्षा हमारे बच्चों को छुटपन से ही काम के लिये नफ़रत सिखाती है और यह भी एक कारण है कि आज इस कदर बेकारी फैल रही है। आज की शिक्षा में काम करना, मेहनत करना, अप्रतिष्ठा का नमूना समझा जाता है। कम उद्योग अधिक इज्जत। आज हमारे मुल्क में यह देखा जाता है कि बिना काम किये पढ़े लिखे लोगों को अधिक इज्जत मिलती है, बैठने को कुर्सी मिलती है, तो हर आदमी यही चाहता है कि बस यही करना चाहिये, इसलिये सब का ऐसे पढ़ने की ओर ही ध्यान जाता है। और पढ़ लिख जाते हैं तो नौकरियों के पीछे जाते हैं क्योंकि काम के लिए उनके दिल में नफ़रत पैदा हो गई, श्रम की प्रतिष्ठा जाती रही। यदि इस देश में फिर से श्रम की प्रतिष्ठा को लाना है तो आपको बैसिक एजूकेशन पहिले लाना होगा। उद्योग के ज़रिये आपको प्राथमिक शिक्षा देनी होगी, क्योंकि बद्धि और हाथ पैर का परस्पर सम्बन्ध है और जब तक बुद्धि और हाथ पैर का परस्पर सम्बन्ध नहीं सिखलाया जायेगा, तब तक आप श्रम की प्रतिष्ठा यहां पैदा नहीं कर सकते हैं। बुद्धि और हाथ पैरों का सम्बन्ध वैसा ही है जैसा अन्धे और लूले का होता है। अन्धा लूले के बगैर देख नहीं सकता है और लूला अन्धे के बगैर चल नहीं सकता है। इस तरह से अगर हाथ पैर बुद्धि की उपेक्षा करते हैं तो वे निबुद्धि हो जाते हैं। और यदि बुद्धि हाथ पैरों की उपेक्षा करती है तो वह निकम्मी हो जाती है। इसलिये ऐसी शिक्षा होनी चाहिये जिससे बुद्धि के साथ साथ शरीर को परवरिश मिले। हाथ, पैर, आंख, कान इन सब का उचित उपयोग हमें शिक्षा ही सिखला सकती है। जिस शिक्षा द्वारा हमें इन तमाम इन्द्रियों का उपयोग सिखाया जाता हो, ऐसी शिक्षा छुटपने से ही दी जानी चाहिये। क्योंकि अगर छुटपने से ही ऐसी शिक्षा दी जायगी तो वह आखिर तक काम में आयेगी।

आप जानते हैं कि श्रम की महत्ता इस देश में से उठ जाने के कारण कौन कौन सी आपत्ति आई हैं। हम फिर से श्रम की प्रतिष्ठा इस देश में लाना चाहते हैं इसलिये छुटपने से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उन उद्योगों की तालीम देनी चाहिये जिन उद्योगों द्वारा उन्हें आगे चलकर मदद भी मिले। इसके साथ ही साथ हमें उनको इस तरह की शिक्षा देनी चाहिये जिससे वे अपने जीवन में अपने खानदानी उद्योगों को भी समझ सकें। हमें श्रम को महत्ता देनी है और देश में कलमदां को ही मुख्य नहीं बनाना है। इस तरह से हम को बेसिक एजूकेशन द्वारा देश को बदलना होगा।

इस देश में जो आज "मूल्य" हैं, वह भी बदलने होंगे। आप जानते हैं कि इस श्रम की अप्रतिष्ठा के कारण हमारे शिक्षित भी निठल्ले बन गये हैं। यदि आपको इस देश में फिर से पुरुषार्थ पैदा करना है, तो बेसिक एजूकेशन शीघ्र कार्य रूप में लाये बगैर कोई चारा नहीं है। हमें बेसिक एजूकेशन के मारफ़त ही छुटपने से ही मनुष्य को इन्सान बनाना है। आज इन्सानियत इन्सान से बहुत दूर जा रही है। इन्सान की इन्सानियत दिन प्रति दिन कम हो रही है। हम ऊंचे उड़ रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, परन्तु पड़ोस में क्या हो रहा है, यह नहीं जानते हैं। । कुछ दिन हुए हमारे माननीय उप-राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने सत्य ही कहा था :

> "We have learnt how to fly in the air and how to cross the oceans but we have yet to learn how to walk on the earth with human beings."

हम आकाश में उड़ रहे हैं, समुद्र को लांघ रहे हैं, परन्तु ज़मीन पर चलना नहीं जानते। यदि आपको ज़मीन पर चलना सीखना है तो आपको मनुष्यता सीखनी होगी, इन्सानियत सीखनी होगी, पड़ोसी धर्म सीखना होगा। यह तभी हो सकता है, जब उद्योगों द्वारा हम छुटपने से ही शिक्षा दें। इस दुनिया में हर-एक का उपयोग है और अगर हम उस चीज़ को अपनायेंगे तब समाज भी उसको अपनायेगा। बढ़ई, लोहार आदि हर एक का जीवन में एक स्थान है और वह सब के ही काम आता है। अगर हम उसकी इज्जत करेंगे तो उसके दिल में भी सब के लिए प्रतिष्ठा पैदा होगी। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए ही लोगों के दिलों में प्रतिष्ठा नहीं होगी बल्कि जो देहातों में छोटे छोटे काम करते हैं उनके लिए भी इज्ज़त बढ़ेगी।

इस देश में बेसिक एजूकेशन का प्रयोग कई राज्यों की ओर से किया जा रहा है। कई राज्यों ने बसिक एजूकेशन के लिए एक कमपैक्ट एरियाज़ (compact areas) में बेसिक मदरसे खोल रखे हैं। बहुत से मदरसों और पाठशालाओं में कृषि का कार्य चलता है परन्तु जिस तेजी से व लगन से काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। उसका सबब क्या है, उन कारणों पर हमें विचार करना चाहिये। पहिली बात यह है कि बेसिक एजूकेशन देने के लिए हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं हैं। आज के हमारे जो शिक्षक हैं वे बिचारे पहिले नौकरी की तलाश में सब तरफ जाते हैं, जब उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कहीं आश्रय नहीं मिलता है तब वे हारे के दर्जे प्राथमिक शिक्षक बनते हैं। सब जगह निराश होने पर यहां उन बिचारों को तनख्वाह मिलती है २५ रुपया। आज हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे राज्य हैं, दो या तीन, जहां माहवारी तनख्वाह २५ रुपया है। दो राज्य ऐसे हैं जहां माहवारी तनख्वाह ३० रुपया है। तीन ऐसे राज्य ह जहां ४० रुपया माहवारी तनख्वाह मिलती है। यानी मतलब यह है कि २५ रुपया से लेकर ४० रुपया तक प्राथमिक शिक्षकों को माहवारी तनख्वाह मिलती है। मेरे ख्याल से हैदराबाद स्टेट (State) ही एक ऐसा राज्य है जहां प्राथमिक शिक्षकों को ६५ रुपया माहवारी मिलता है। इधर जब हम नई दिल्ली के दफ्तरों में जो पियन्स (peons) हैं, उनकी तनख्वाह को देखते हैं, तो उनको माह में ८०–९० और १०० रुपया तक मिलता है। मगर जो हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जो हमारे समाज के आधार स्तम्भ हैं, जो हमारी भावी पीढ़ी को बनाने वाले हैं, जिनके ऊपर देश का बनना बिगड़ना निश्चित है, उनको खाने को भी पूरा नहीं मिलता है। तो आप ही बतलाइये कि वह किस तरह से बेसिक एजूकेशन चला सकते हैं और किस तरह से प्राथमिक पाठशालाओं को अच्छी तरह बना सकते हैं।

यह तो शिक्षकों की बात हुई। अब अधिकारियों को लीजिये जिनकी तनख्वाहें काफी होती हैं। आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट (department) के अधिकारी से पूछिये कि क्या उनकी बेसिक एजूकेशन पर श्रद्धा है। सच में उनकी श्रद्धा नहीं है।

(Time bell rings.)

SHRI D. NARAYAN: Five minutes please.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken more than five minutes now.

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : उनको डर है ऐसा होने से उनकी साहबी उनसे जाती रहेगी। वह अपनी साहबी छोड़ना नहीं चाहते; बेसिक एजूकेशन उन्हें पसन्द नहीं हो सकती। उनको तो बेसिक शिक्षा प्राप्त करनी नहीं, व तो

[Shri D. Narayan.]

पढ़ चुके, परन्तु उन्हें कुछ न कुछ व्यवस्था तो चलानी है और उसके लिये आपकी ओर से इंसपेक्टर्स (inspectors) बने हुए हैं। तीसरी बात जो इस प्रस्ताव में कही गई है उसकी व्यवस्था के बारे में पंचवर्षीय योजना में एक जगह लिखा हुआ है :

"Basic education being a new experience, it is essential in the initial stages to create a strong nucleus by having a separate unit for it within the Education Department."

एक बात और मुझे कहनी है। दस बरस में हमें देश में सर्वत्र फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन करनी है, तीन बरस बीत गये, अब सात बरस में यह काम कैसे हो सकेगा। इसके लिये कुछ विचार होना चाहिये और कोई कमेटी (committee) आल इंडिया (all-India) स्वरूप की बनाई जाय, जो कि इन तमाम बातों पर गौर करे। लेकिन यहां तो उलटी गंगा बहती आई है। जहां तक कि शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है, एक मराठी में कहावत है : "आधी कलस मग पाया रे"। यानी पहले कलश बनाया जाता है और फिर नींव की बात सोची जाती है। यूनिवर्सिटी कमीशन्स (University Commissions) कायम हुए, सेकेन्डरी कमीशन्स (Secondary Commissions) कायम हो चुके, परन्तु जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, उसके लिये कोई कमीशन आज तक कायम नहीं हुआ। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपको सात वर्ष में यह काम करना है तो आप ऐसी योजना तैयार करें जिससे यह उसी अवधि के अन्दर काम पूरा हो जाय।

आपने जनराज्य तो कायम कर दिया और जनराज्य का नियम है कि जैसी जनता होगी वैसा ही राज्य का स्वरूप होगा। अगर आप इस जनराज्य को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं तो आपको जनता को शिक्षित करना होगा और इस निगाह से आप इस प्रश्न को सोचियेगा, यह न सोचें कि मुट्ठी भर शिक्षितों की जो मोनोपली (monopoly) है वह सदा चलती रहेगी और डिमोक्रेसी (democracy) के साथ खिलवाड़ की जा सकेगी। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस तरह से जनता के साथ खेल न खेलें, जनता को, देहातियों को शिक्षित करें और उन्हें जनराज्य के योग्य नागरिक बनायें। अन्त में मेरी एक ही प्रार्थना है—चेतावनी कहिये—और वह डा० राधाकृष्णन जी के ही शब्दों में है कि :

"Our whole experiment in democracy will suffer if education is not given top priority."

आपको एजूकेशन को टौप प्रायरिटी (top priority) देनी होगी। मेरी यह अभिलाषा थी कि हमारे बुजुर्ग माननीय मंत्री जी भी यहां उपस्थित होते, उनसे इसके लिये प्रार्थना भी की थी कि वे उपस्थित रहें, परन्तु दुःख की बात है कि यहां आने के बाद वह फिर चले गये।

SHRI C. G. K. REDDY (Mysore):

श्री सी० जी० के० रेड्डी (मैसूर) बिजी (busy) आदमी है, साहब।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : मुझे विश्वास है कि यहां जो कुछ भी इस विषय में बातें होंगी माननीय मालवीय जी उनके कानों तक पहुंचा देंगे। आशा है कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और यह जो जनता की आवाज है, जनता की आकांक्षा है और मांग है, उसको पूरा करेगी।

एक प्रार्थना, श्रीमन् डिप्टी चेयरमैन साहब, आपसे है कि इस प्रस्तावपर चर्चा के लिये

दो ही घंटे मिले हैं । यह प्रस्ताव दो घंटों की चर्चा में तो खत्म हो नहीं सकता क्योंकि बहुत से सम्माननीय सभासदों को इसमें हिस्सा लेना होगा । मैं आशा करता हूं कि साढ़े छः बजे बाद यह अगली दफा के लिये मुल्तवी कर दिया जायगा ।

[For English translation, see Appendix VI, Annexure No. 90.]

MR. DEPUTY CHAIRMAN Resolution moved:

"This Council is of opinion that Government should take early steps—

(a) towards the implementation of the provisions of article 45 of the Constitution of India, and

(b) to declare basic education as the pattern of national system of education to be hereafter established in India.

This Council is further of opinion that Government should immediately establish a basic education section in the appropriate Ministry for co-ordinating and circulating useful information to the States with regard to basic education and for serving as a liaison with training institutions and educational departments."

There is an amendment by Prof. Malkani.

PROF N. R. MALKANI (Nominated): Sir, I move:

"That for the second paragraph of the Resolution, the following be substituted, namely:—

'This Council is further of opinion that Government shall hereafter issue clear instructions that all new primary schools, more specially in the community project areas, shall be of the basic type. Government shall also take early steps to convert existing primary schools into basic schools.'"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Resolution and the amendment are open for discussion. Shri Malkani.

PROF. N. R. MALKANI: Sir, I consider this Resolution as a very important Resolution. I don't want to tell you about the evil effects of the present system of education and waste your time. They are well-known to all. Education means the development of man's faculties according to his special aptitudes. But it is also a call for life. In modern language, it is a call for life through work. Every time in the life of mankind there is a call for life which is called the call for a higher life, the call for a nobler life and education shapes itself to meet that call. That call permeates all life and education is moulded according to the call of that age. In the Mahabharata days—I am sorry to take you back so far—it was a call for being a warrior. Then to be a *Kshatriya* was an honour and the best education was that of a *Kshatriya*. Later on the *Brahmins* came The call was for purity, for learning and preservation of the Aryan tradition and the *Brahmins* came to the top and the best education was that of the *Brahmins*. They were the best educated in India. Later Buddhism came and the best call for life was the life of the mendicant, of a *bhikshu*, and education was according to the need of the mendicant's life. Later on we come to the Muslim period and then something novel happened to India. The call was to be a *bhakta*, a devotee, devotee of God. Literature and art were the hand maiden's of *bhakti*. The most devotional songs—and they are the very best—are of that period. Then we come to the British age and modern life. It was a new epoch in our life. The call of life under the British was for educated clerks, known as educated babus. So in fact we got third class men, second class babus and first class Mimics of the West. That is even so today. But today after independence, what do we have? We all are—whether we wear suits or dhoties—*Banias* at heart. We all want to make quick money—either as politicians or as businessmen. Education has become purely utilitarian. No nation can accept that and progress forward. Therefore, our best

[Prof. N. R. Malkani.]

man has set for us the highest call of life. When he was asked "Who are you?", Gandhiji said—I think you all remember, what he said—"I am a farmer and a weaver". It was in 1920 or so. Before he died we asked him "What are you?" and he said "I am a model *bhangi*". He set a noble tone, a higher tone and he asked us to adjust everything—our education, our economic system, our social reforms to that tone. He asked us to become model *bhangies* in the symbolic sense—not only *bhangies* with the broom, but *bhangies* of society, *bhangies* of the economic organisation and be clean, white clean, in the symbolic sense. That is the tone set for us and we have got to obey it. It must be obeyed. We cannot last as a nation by being *banias* and babus. We have got to be model *bhangies* in the truest sense and our education must be toned up if we are to live. You all know very well that our education is inadequate in this. But the greatest harm that our present education has done is this. It has made us strangers in our own homes. It has made us outsiders in our own villages. The villages are becoming depopulated and demoralised and every villager wants to migrate to the towns because our attention has been given to the town. If I were to use a simile, I would say that our educational system is playing *sirshasan*—standing on its head. Generally we walk on our legs and sometimes a queer one like myself stands on his head for a minute or two so that he may walk properly on legs during the rest of the 24 hours. But our whole educational system—as also the economic and social system—is standing on its head for 24 hours minus two minutes on its feet.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. C. GHOSE) in the Chair.]

5 P.M.

It is top-heavy. It has produced strange babus. It does not think of the man of the soil, it does not think of the people in the village, of the masses. It does not think of them at all. The result is what happens to a man who always stands on his head—the limbs are weak, the heart has no blood, he has a bloated and swollen head. We have all swollen heads. We are proud of our intelligence, but we have no blood in the heart and the limbs are weak and the head is large. The hon. Minister for Education is not present to hear me, but I repeat that our educational system is tottering on his and our heads too. Let him take note of it, that the body politic, the social community is tottering on our heads because of our existing education. Does it need a few more riots to wake us up?

I now come to my next point. I have gone round and seen some people in our villages. I talk to the poor folk there and ask them what they want. Invariably they say, "Give us a well here and a canal there." And immediately after they say, "Give us a school." That is what they want most. Today all over the country there is a great and keen demand for irrigation first and immediately after that for schools. And I have seen a few strange things too. I went to a small village in Kutch called Gorpadi. I wish the hon. Minister were present there when I had a cup of tea with them, on the ground of their school. There they had built a school building 60 ft. broad, 19 ft. high and 90 ft. long with Mangalore tiles on the roof and all built in just 33 days. Remember they did it all in 33 days and it was a little palace in that poor village. As for the cost, Rs. 9,000 were paid in cash down by the villagers and Rs. 3,000 in labour of fifty persons working for 33 days. It was a marvel of achievement due to the enthusiasm of the people. That is the state of enthusiasm of the people in India and that is happening all over the country on a larger or a smaller scale. And then when tea was over they showed me the teacher—an old man, full of grey hairs, in dirty clothes

He was supposed to be the teacher for the new school. That broke my heart. That will break anybody's heart. Here was an untrained old, single teacher with about a hundred children romping in the classes. The next point is the size of the problem, which is a little staggering. If we are going to implement this article of our Constitution in spirit as well as in form, by giving free and compulsory education to all pupils between the age of 6—14 years, then their number will be 6·87 crores or say 7 crores! And the money required will be about Rs. 400 crores. But our total budget on all education is only for Rs. 103 crores and strangely enough, we are spending Rs. 50 crores on secondary and then higher and technical, technological and polytechnical education and all this without carrying out the programme for free and compulsory education. That will require Rs. 400 crores plus Rs. 272 crores for buildings and Rs. 200 crores more for the training of the required number of teachers and so on. Immediately the hon. Minister will ask me. "Malkani, you are talking what you do not understand. Don't you see these huge figures? Where is the money to come from for your education? It cannot be done." But I say, you, and I and all of us are here to get this thing done, not to say that it is difficult, that the difficulties are insuperable, that it is impossible. I say it is possible and it can be done. You wanted Rs. 2,000 crores for the Five Year Plan and you get it somehow, you wanted it and so you beg, you borrow and so it is there. In the same way we have to find out the money for this. If you have no money, find it out, go and borrow it or beg for it or take it from the people. But I say, you can find all the money that you need and I am going to tell you how.

Proceeding further, I take up the observation of my hon. friend Shri Saksena who asked, "What is this wretched basic thing that... ..

SHRI H. P. SAKSENA (Uttar Pradesh): I did not say "wretched".

PROF. N. R. MALKANI: All right, he said what is basic, what is fundamental about it? I say it is basic and fundamental because it is integrated education for eight years, not education for one, two or three years only. It is integrated, free, compulsory education for eight years. Secondly, as I put it, it is purposeful education through mental and manual activities, so as to make the pupils self-reliant servants of society. They should not only be self-reliant, but they should also be servants of society—*Samaj-Sewaks*. They will have eight years of free compulsory education entailing work of both the hands and the head for the purpose of serving society. They will thus get a sense of social consciousness, not of this family or that, but of a new society, the society called "*Sarvodaya*" based on the good of all. It is basic because it develops these social faculties in the mass of our boys and girls and develops them into self-reliant servants of society—*Samaj Sewaks*. Basic education must be based on the service of all.

Sir, I shall now go to the next point. The Central Advisory Board of Education approached this question of basic education in the most sceptical manner and after some discussion of its financial and 'productive' implications rejected it in 1944. In 1949, however, light dawned on them and they said that the experience gained so far was fairly good and the departments should further explore the remunerative aspect. Then in 1950 they went a step further. In 1951 a questionnaire—as is usually the case—was issued and an official committee was appointed to investigate the 'productive' part of the scheme. That committee gave a thundering report and not only said that the thing could be done but that it was the best kind of education. In 1952, the Central Advisory Board said, "The element of craft work is of such importance that even if expenditure is involved, it is necessary to replace ordinary education by basic education in a planned manner." They also said, "The pace of progress

[Prof. N. R. Malkani.]

of basic education needs to be accelerated; special measures should be taken for training the necessary staff"; and that "Progress was not as satisfactory as it might have been, because the funds provided were quite inadequate for the purpose."

Sir, I have simply summarised the findings of the Board in a few lines.

Now I come to the question: Where is the money to come from? I tell you, the cost is large, but if you have the good sense and approach the problem in the right way, the problem of cost will not stand in the way. Let us break it up into two parts—the recurring and the non-recurring cost. Let us take the non-recurring part first. You require for a junior basic school of 5 classes Rs. 4,000 for equipment and buildings and Rs. 2·5 acres of land. If it is to be an agricultural school, it will be Rs. 4,000 plus 5 acres of land. For a senior basic school of 8 classes, you want Rs. 12,500 plus 5 acres of land and if it is an agricultural school, 10 acres of land. Now, you might say this is an enormous thing. But as I told you just now, so far as buildings are concerned, you have only to ask for them and the villagers will put up the building without any cost whatsoever to you or the cost will be negligible. Further, in the villages the people have become more generous about land. Vinobaji has produced an atmosphere, a marvellous atmosphere and they are generous even with their little land. You ask for five acres of land for a school and they give it to you. After all for the basic schools you want very little land and you will get it almost free. The total land that you want is about 3 million acres which is only less than 1 per cent. of the cultivated area. If you approach Vinobaji, if you approach the villager himself in the proper attitude with the proper enthusiasm, you will get the land, almost free and the buildings would be built. Of course, the equipment will cost you something but that of course my hon. friend should be able to supply. You give them the tools and raw materials and they will do the rest themselves. That way, the whole problem can be reduced to a very small manageable proportion. But the first problem is putting some blood in your heart to feel warm standing on your feet to work with your hands and then going to the people and asking them for land and buildings. All this should not at all be difficult. The special Committee which was appointed said that in a good average school in Brindaban (Bihar) the total costs were recouped by 67 per cent. Regarding cost, my hon. friend, the mover of the motion said that each pupil today cost Rs. 16 per year but my information is that it is more than Rs. 20. Of course, teachers will cost a little more in basic schools but there is a big difference in all the other things.

(Time bell rings.)

Kindly give me five minutes more, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. C. GHOSE): I have already given you five minutes more.

PROF. N. R. MALKANI: It is my Resolution, Sir. You must treat it as such.

PROF. G. RANGA (Andhra): Give him five minutes more, Sir. It does not matter.

PROF. N. R. MALKANI: So far as the recurring costs are concerned in basic education, if it is properly run, 60 per cent. can be recovered in a good average school. In the most miserable schools it is about 10 per cent. and in good schools it is 67 per cent. and the average here and there all over the country would be 20 to 25 per cent. But all this is being done half-heartedly, in a most shabby manner. It can be done very well on three conditions. The conditions are: The schools must be for 8 years, properly integrated, not three years, or two years or less than that. And those miserable one teacher schools should be replaced by real schools of 8 classes so that in the

higher stages the boys work better. Secondly, there should not only be eight-class schools but there must be proper attendance of 30 boys in a class. For an eight-class school, the total will be 250 pupils attending regularly. That can only happen when the children produce their own fruits and vegetables in the school garden, produce their own clothes in the workshops, or go home and work with their parents. Then, the attendance will be good. But the daily attendance should be at least 30 in a class, not less. Lastly, they should be properly equipped. Sir, these are the three necessary conditions. If you really want good basic education, not one of these conditions can be omitted. And may I tell you, Sir, that not one of these conditions is today being properly implemented?

It is very shameful reading but I have got the report of the working only a few days ago. The total number of junior schools in the whole of India, Sir, is 1386, the number of pupils is 1,22,825 and the total expenditure is Rs. 40 lakhs. The number of senior schools all over the country is 420 with a total strength of 76,038 pupils and a total expenditure of Rs. 26½ lakhs. With this miserable sort of thing can you say that you have really taken up experimenting in basic education with any enthusiasm? This is just playing with the scheme. Better reject it outright rather than this which is neither rejection nor acceptance. It is a sad and miserable thing. If you want to have it, have it in a proper way.

Lastly, Sir, there are two chief obstacles to progress. One obstacle is the teachers themselves. It is difficult to convert an ordinary teacher into a craft teacher or a craftsman into a basic teacher. And the second difficulty, which is a greater difficulty, is in the educational services. Among those who man the Education Department, I have yet to find a Director of Education or a Deputy Director of Education or an Inspector of Education who really believes in it. He not only does not believe in it but he almost rejects it.

SHRI D. NARAYAN: He does not understand it.

PROF. N. R. MALKANI: That is better, it is very generous to him today that he does not understand it but if he understands and rejects it, so much the worse for him. Ask him where his son is being educated? May I ask, Sir, some of our friends, "Do we send our children to the basic schools?" We live round the towns, where do we send our children? I ask the Minister himself, where does he send his children?

PROF. G. RANGA: He has no children, I suppose.

PROF. N. R. MALKANI: It is not only the services which dislike the system. They do not obstruct the system but they simply reject it. There is not one educationist that I am aware of, and I can challenge the Minister also, to say that the basic education system is bad. Everybody knows and says that it is the most *marvellous thing but progress is* the most miserable that I know of. No educationist that I know of has anything but praise for the system, the principle which was given to us by Gandhiji, but no one has any praise for the actual achievement because nobody believes in it, nobody takes the trouble of implementing it. We are all steeped in the West. We are so steeped in the West that we think and act like the Westerners and so naturally we cannot accept the gold which is with us. We ourselves think that it is less than copper. At the top, the people at the very top, the Secretaries; the very Directors, do not take any interest. May I say that there is progress only where the Minister or the man at the top has faith in it. It may succeed because it is a Kher who is behind; it may succeed because it is C. R. who has faith in it and he will make a success of it. Otherwise, it is a miserable failure because either the Director does not do it or the Secretary rejects it or the Minister does not agree.

(Time bell rings.)

[Prof. N. R. Malkani.]

I need not take more time, Sir, but unless these steps are taken one by one, unless you put your heart and soul in it, unless you do it with vigour and enthusiasm you cannot make progress. It is no use talking about it. If you reject it that will be good for we will then know where we stand. We passed a tremendous resolution the other day in the Congress Working Committee. I do not want to read it here but it is a tremendous resolution. Never has the Working Committee passed such a resolution on education. Dr. Radhakrishnan the other day gave such an impassioned speech which I listened to on the radio. It sounded like a young man throbbing with emotion who was talking. But what is actually happening to our education? We have got to put our hands and hearts to it and then, I hope, Sir, things will begin to move.

SHRI H. C. MATHUR (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, I support this Resolution and I welcome it. I welcome it as a motion of no confidence in the Education Minister and if we are honest to ourselves and using a milder term, it is nothing else but a motion of censure at least. The hon. Deputy Minister who spoke only a few minutes back told us, that he felt very much hurt at the bitter remarks made by some of his Congress friends while speaking on the other Resolution. But I wish, Sir, that he has disillusioned himself and that he knows what the feelings are about the working of his Ministry. It is something about which everybody feels not only dissatisfied and disgusted but there are sections where the feeling is that there is a cold and calculated obstruction in this Ministry for all sorts of reforms. Sir, It is of course obvious and evident to everyone that education to a nation is something more important than anything else and I believe, Sir, everybody would agree that the first demand of freedom is universal education. Democracy itself is in danger without the education going down to our rural areas and until and unless education is made universal and compulsory, we must not rest content and we must be aware of the danger that is before us. There are many aspects of this Resolution and this is one aspect about which I would first like to emphasise. My interest has not been roused only by this Resolution. As a matter of fact I felt very much that so little was done or practically nothing was being done in the field of education.

About a year back I wrote a letter to the Education Ministry enquiring as to what was being done, more particularly, in the sphere of primary and basic education and the reply which I received was that, so far as the basic and primary education was concerned, they depended on the post-war educational development in India contained in a report of the Central Advisory Board of Education which was submitted sometime in January 1944. They said that that report had been accepted and they were proceeding on the basis of that report. Sir, I would like to invite the attention of the hon. Deputy Minister to this very report, and this report regarding basic and primary middle education opens with a very disquieting remark. That is: "In every country of the world, whether occidental or oriental, which aspires to be regarded as civilized, with the exception of India, the need for a national system of education for both boys and girls which will provide the minimum training, for citizenship, has now been accepted. In India the need for a similar provision has been under discussion for many years, but that no substantial progress as yet has been made is obvious from the fact that over 85 per cent. of her population is illiterate. Any country so situated is a potential source of danger under modern conditions, and when the country is or aspires to be a democracy, the position becomes worse than dangerous. The primary requisite of any system of public education for a democracy is that it

should provide for all its members and not for a few only, at least such training as may be necessary to make them reasonably good citizens." So according to the report which has been accepted by the Government and which is their sole guide, we are living in a state of perpetual danger. Sir, I have also gone through the report of this Board placed in the library from year to year. I need not advance any arguments or quote any facts and figures. Even a reference to this report would be enough to convince everyone here that the progress in this direction has been absolutely miserable. This is a thing which cannot be challenged even by Government, and the argument advanced is that financial stringency is one of the reasons. Sir, how disappointing it is to find that even after full six years of our freedom we find ourselves in a state of affairs which is at once humiliating and of which all of us feel quite ashamed. This is only the political side of the question, Sir, but this political side of the question is so related to every thing which matters that we cannot ignore. The human side of it, of course, is obvious and evident. Everybody, we cannot deny, has a right to be educated. Our Prime Minister, while speaking on this subject only a few days back, said that he was simply amazed when he went to the villages to find in the rural population a great urge for schools and for education and that they were more than prepared to contribute their share in the shape of voluntary labour and contributions. But how unfortunate it is that the Ministry has absolutely failed to mobilise and make use of that enthusiasm which already exists.

Sir, the mover of this Resolution, who quoted figures very properly, gave the necessary information, and I find that Rajasthan, the State from which I come, is at the lowest rung of the ladder. It is not only for the first time that we know this unfortunate fact from the mover of this Resolution. We have been, as a matter of fact, pressing this thing before both, the State Government as well as the Central Government. Sir, I took all the pains to collect all the information and submit a note to the Gadgil Committee which was appointed to see how these Part B States could catch up with the other Part A States. Not only had I quoted these very facts and figures but I had told them how great the need of Rajasthan in the field of education was. I am really ashamed to have to tell you that instead of new schools coming up there have been hundreds of schools which have even been closed down during the last year and a half.

PROF. G. RANGA: Something wrong with your local leaders.

SHRI H. C. MATHUR: It was only because those schools were running on private charity and the necessary Government-aid which those schools demanded could not be provided. When the States were integrated it was a definite promise given to us that our needs would be enquired into and that necessary provision would be made to enable us to take the necessary steps. We were well on our way, I can tell you, particularly about the Jodhpur State. Now the overall position of literacy in Rajasthan is 8 per cent. It was about 15 per cent. in the Jodhpur State, Sir, and if the progress had gone according to the schemes and the sanctions which we had in hand at that time and if the plan which we had then had been adopted, today the situation would have been entirely different. I wish the Centre realises this responsibility. By bringing about this integration they have taken upon themselves a great responsibility to help these States, at least to meet the most fundamental and primary demands of these States. It is no use getting up here and telling us that Rajasthan is the most backward State and there are only 8 per cent. people who are literate there. I submit, Sir, since integration, the progress of this State has been halted and we have been going step by step,

[Shri H. C. Mathur.]

and here particularly comes the responsibility of the Centre.

About this basic education, Sir, there is very little argument which has got to be advanced. But I do not agree with the previous speaker when he says that most of the expenditure to be incurred on basic education could be met by the disposal of the products from those schools. If you go and hob-nob with the educational system just to get more money out of it, you will be making a complete mess of it. As a matter of fact, the expert committee, to which I had referred in the report, which has been accepted by the Government, has gone into this question very carefully and has given its verdict on this particular issue. Let there be no misunderstanding about it. But still when we examine the figures, when we know the amount which is being spent on education, we find that if there is any field which has been neglected, it is the field of education. Sir, anybody who is conversant with the history of free nations will tell us that the first and foremost thing which they have tackled, whenever they wanted to bring about any change in society, was education. Because only through the agency of education can we bring about a real change in the position of our society. Hitler did it. I do not mean to say that we should follow those very methods. But if we are going to have a new educational system, if we want to have a change in it—which all of us aspire—then only through this national system of education, we can achieve something and it is only here that we have miserably failed. I know, Sir, I am doing a little injustice to the Education Ministry because it is possibly too much to expect such dynamic changes from a Ministry which has got no vigour. It is really unfortunate. We must have in the Education Ministry some dynamic personality who could put in relentless work and who could bring about revolutionary changes, but, as I said, it is injustice to expect much from the Ministry. But, greater injustice is being done to the country, and the youth and the children of this land, who have been neglected and betrayed during these six years of freedom. They will never forgive and forget it.

SHRI K. D. MALAVIYA: It is all very well to hear all these denunciations and rancorous talks, but may I have the privilege of hearing from the hon. Member something about some concrete suggestions that he could place before the House? That is, if you could know anything, because we are all interested so much in this subject.

SHRI H. C. MATHUR: I can certainly give any number of concrete suggestions. I can submit proposals and put things through.

AN HON. MEMBER: But are they able to act upon them?

SHRI H. C. MATHUR: As a matter of fact, we have been doing it in Jodhpur. I was myself Minister of Education in those days and I have put through vast schemes. If they had been followed up, today the percentage would have been at least 25.

PROF. R. D. SINHA DINKAR (Bihar): **प्रो० आर० डी० सिन्हा दिनकर** (बिहार): श्रीमन्, बुनियादी तालीम आज इस अवस्था में नहीं है कि उसकी अच्छाइयों को साबित करने के लिये हम दलील ढूंढें, क्योंकि जबसे इस तालीम का आरम्भ हुआ, तब से अनेक प्रान्तों मे अनेक समितियों में अनेक शिक्षा विशेषज्ञों के द्वारा इसकी परीक्षा हो चुकी है और अब यह शिक्षा प्रणाली सरकार ने स्वीकार कर ली है। अब यही राष्ट्रीय शिक्षा का वर्तमान रूप है। अगर कोई शंका की बात होती तो पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तालीम को वह स्थान नहीं मिलता जो कि उसे दिया गया है। पंचवर्षीय योजना में दो बातें बहुत ही प्रमुखता रखती हैं। एक

तो कृषि उद्धार और दूसरी शिक्षा सुधार के सम्बन्ध में बुनियादी शिक्षा का प्रसार करना। तो जहां तक बुनियादी तालीम की अच्छाइयों और उसकी खूबियों का सवाल है, मेरा ख्याल है कि ऐसे कोई भी सज्जन नहीं हैं जो उसकी खूबी में विश्वास न करते हों। बात वहां नहीं अटकती है। वह तो कहीं और ही जाकर अटकती है। कहां अटकती है, यह मैं पीछे कहूंगा।

मैंने अपने यहां एक दो स्थानों पर स्वयं इस शिक्षा को देखा। एक आध बार मेरे जिम्मे यह काम भी लगाया गया था कि बेसिक स्कूलों में जाकर देखूं कि वहां के लड़कों की हैसियत क्या है। और मैंने देखा कि जो लड़के सात, आठ साल बुनियादी शिक्षा पा कर के आते हैं, उनमें आत्म निर्भरता होती है। कालेज से जो लड़के निकलते हैं उनकी अपेक्षा उनमें अपने ऊपर अधिक भरोसा होता है। उनमें वह बल होता है जो "कर्म" और "ज्ञान" के मिलने से निकलता है। उनमें मुझे कोई भी इस भय से प्रेरित नहीं दिखाई दिया कि पढ़ने के बाद नौकरी कहां मिलेगी, या अगर बेकारी के चक्कर में फंस गये तो दिन कैसे बीतेंगे। ये सारी दुश्चिन्तायें उनके सामने नहीं हैं। इसको देख कर बुनियादी तालीम की पद्धति में मेरा विश्वास और भी बढ़ गया और मैं मानता हूं कि हठपूर्वक निराशाओं का सामना करके भी असफलताओं को किसी प्रकार सहन करते हुये भी हमें इस प्रयोग पर स्थिर रहना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि बुनियादी शिक्षा के जितने प्रयोग इस देश में हो रहे हैं, उन प्रयोगों की जांच हम किस कसौटी पर करें। कौन सी ऐसी कसौटी है जिस पर जांचने से इस बात का पता लग सकता है कि बुनियादी तालीम सफल हो रही है या असफल हो रही है? मेरा ख्याल है कि बुनियादी तालीम की बात गांधी जी को इसलिये सूझी होगी कि नई शिक्षा से सिर्फ नौकरी करने वाले लोग पैदा होते हैं, कर्महीन लोग पैदा होते हैं और यह देश इतना गरीब है कि उस ढंग की शिक्षा को सर्वत्र नहीं फैला सकता। गांधी जी के सामने दो बातें रही होंगी। एक तो यह कि स्कूल ऐसे हों जो अपना खर्चा थोड़ा बहुत स्वयं जुटा सकें और दूसरी बात यह कि जो लड़के उन स्कूलों से निकलें वे नौकरी की तलाश में न जायें। उनको नौकरी मिल जाय तो ठीक है, नहीं तो वे दस्तकारी करके कमा खा सकें। दुर्भाग्यवश इन दोनों कसौटियों पर जांचने के बाद कुछ ही वैयक्तिक संस्थायें हैं जिनको सफलता का नम्बर दिया जा सकता है, बाकी जितने स्कूल हैं, जितनी पाठशालायें हैं, उनमें असफलता ही प्रधान है। मैं समझता हूं कि सरकार के जो निरीक्षक होते हैं वे सिर्फ यह देख कर चले आते हैं कि दस्तकारी के नाम पर रुई कितनी बर्बाद हुई और जिस स्कूल में लड़के ज्यादा रुई बर्बाद करते हैं उस स्कूल में, वे समझते हैं कि दस्तकारी खूब चल रही है। निरीक्षकों को यह भी तो देखना चाहिये कि जो रुई बर्बाद हो रही है उसकी कुछ कीमत भी आ रही है या नहीं। भारत सरकार का जो भी विभाग बुनियादी तालीम को देख रहा हो, उसका यह कर्तव्य है कि वह देश भर में कान लगाये रहे और चारों ओर आंख बिछाये रहे और देखता रहे कि देश भर में इस शिक्षा के सम्बन्ध में कहां क्या हो रहा है। और जहां भी इस विषय के जो आंकड़े मिलें उनको एकत्र करे और उन्हें देश के सामने रखे ताकि हम यह जान सकें कि बुनियादी शिक्षा की प्रगति कैसे हो रही है।

कई बार मैं सोचता हूं कि असफलता के कारण क्या हैं? जो चीज इतनी अच्छी है कि जो भी आदमी उसे देखता है, वही उसका

[Prof. R. D. Sinha Dinkar.]

प्रशंसक बन जाता है, वह इस प्रकार असफल क्यों हो रही है? मुझे उसके तीन चार कारण दिखाई पड़ते हैं।

पहला कारण तो, जैसा कि मजुमदार साहब ने बताया, शिक्षकों का अभाव है क्योंकि शिक्षा में सबसे बड़ी शक्ति शिक्षक ही होते हैं। यदि शिक्षक योग्य नहीं मिले तो शिक्षा की कोई भी पद्धति नहीं चलेगी। शिक्षकों को तैयार करने में सरकार को जो कठिनाइयां हुई हैं उनका भी हम लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान है। जो पुराने शिक्षक हैं वे नये ढंग की चीज को अपना नहीं सकते, उनकी जैसी आदत पड़ी हुई है उसी तरह चलते जाते हैं। यानी जिस दिन कोई इंस्पेक्टर (Inspector) आ गया, उस दिन लड़कों को कुछ खुरपियां दे दी, वर्गों में कुछ चर्खे भी रखवा दिये और थोड़ी सी रुई भी खरीद करा दी। इस प्रकार दिखावट बहुत होती है और काम कुछ नहीं होता है। जो अफसर हैं वे भी इस भय से भीत रहते हैं कि कहीं हमसे यह दिखाया कि हमारे चलाये हुये स्कूल फेल (fail) करते जा रहे हैं तो हमारी बहुत बदनामी हो जायेगी। इसलिये वे गलत बातें लिख कर सरकार के पास भेजते हैं और जब वे गलत बातें सेक्रेटेरियट (Secretariat) में पहुंचती हैं तब सरकार समझती है कि सब बातें ठीक चल रही हैं।

असफलता का एक दूसरा कारण भी है। और मैं समझता हूं कि मूल कारण यही दूसरा कारण है। अगर गांधी जी को यह भय रहता कि स्वराज्य होने के बाद इस देश में स्वदेशी की भावना नहीं रहेगी, दस्तकारी की भावना घट जायेगी, और लोग अचानक अमेरिका बन जाने का और इंगलैंड बन जाने का स्वप्न देखने लगेंगे तो वे कभी भी इस बुनियादी तालीम की योजना को नहीं निकालते। बुनियादी तालीम की योजना उन्होंने इसलिये निकाली थी कि जो लड़के स्कूल से निकलेंगे वे कुछ दस्तकारी करेंगे और वे जो चीजें बनायेंगे उन चीजों की खपत भी आस पास के बाजारों में आसानी से हो जायेगी। लेकिन जिन लोगों ने पंचवर्षीय योजना बनाई उनका ध्यान इस पर नहीं गया कि बुनियादी तालीम और काटेज इंडस्ट्री (cottage industry) का चोली दामन का सम्बन्ध है। जिस देश में कुटीर उद्योग की उपेक्षा की जाती है उस देश की सरकार को कोई हक नहीं कि वह बुनियादी तालीम की योजना चलाये क्योंकि अगर स्वदेशी की भावना खत्म हो गई तो फिर स्कूलों में दस्तकारी से जो चीजें बनेंगी उन चीजों को पहिनने के लिये और खरीदने के लिये कौन तैयार होगा? ऐसी हालत में वे स्कूल तो असफल होंगे ही। ऐसे स्कूल से निकले हुये दस्तकार आगे कुछ नहीं कर सकेंगे और उनका भी वही हाल होगा जो कि आजकल स्कूल से निकले हुये लड़कों का हो रहा है।

इसलिये मेरा एक सुझाव है। आज सुझावों के लिये मंत्री महोदय ने कई बार आवाज उठाई है। मेरा सुझाव यह है कि भारत सरकार अपने को चाहे जैसी भी हो रखे, लेकिन राज्य सरकारों में बुनियादी तालीम और काटेज इंडस्ट्रीज के पोर्टफोलिओ (portfolio) को एक में मिला दिया जाय। जो मंत्री काटेज इंडस्ट्री के हों वही बुनियादी तालीम के भी मंत्री हों, और जो मिनिस्ट्री (Ministry) काटेज इंडस्ट्रीज को चलावे, वही बुनियादी तालीम को भी चलावे। दोनों विभाग एक हों, जिससे कि सरकार को पता चलता रहे कि जिन स्कूलों में किसी खास दस्तकारी का प्रयोग कर रहे हैं उसका वहां क्षेत्र भी है या नहीं, स्कूल से बाहर उनके उत्पादन की खपत

होगी या नहीं । बाहर के औद्योगिक क्षेत्र को दृष्टि में रख कर जब स्कूल चलाया जायेगा तभी सफलता मिलेगी अन्यथा सफलता मिलने की कोई विशेष आशा नहीं है ।

एक और चट्टान है जिस पर आलोचना इस योजना के टूट जाने की आशंका है । वह चट्टान है जनता का अविश्वास । एक बार पहले भी मैंने इस सदन के सामने यह बात कही थी और उसको आज मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि साधारण जनता के मन में यह बात बैठ गई है कि समाज के ये बड़े-बड़े लोग अपने बाल-बच्चों के लिये तो पुरानी शिक्षा रखेंगे और हमारे बाल-बच्चों के लिये निम्न कोटि के स्कूल देंगे क्योंकि वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब दिन नीचा काम करते रहें, मोटा काम करते रहें और जो ऊंचा काम है, महीन काम है, वह सब दिन इन बड़े बड़े लोगों के जिम्मे हो जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहिनते हैं, बड़ी-बड़ी मोटरों पर चलते हैं और जो मोटर भी अपने हाथ से नहीं हांकते । जनता बराबर इस तरह के आक्षेप करती है । मैं पूछता हूं, इन आक्षेपों के जवाब भी हैं ? उनका जवाब न तो भाषणों के द्वारा और न प्रचारों के द्वारा दिया जा सकता है । उनका जवाब वह भाव है जिसे हमारे प्रधान मंत्री ने पहले कृषि-विभाग की कान्फ्रेंस (Conference) में और फिर इंजीनियरों की कान्फ्रेंस में व्यक्त किया है । यह नेकटाई (neck-tie) की मनोवृत्ति छोड़ो, यह विदेशी भाव और साहबी ढंग छोड़ो, तभी जनता तुम्हारा विश्वास करेगी । प्रधान मंत्री में यह विशेषता है कि वे दिल्ली में रहते हुये भी दिल्ली के रेशमी घेरे से अपने को बाहर ले जाकर देश के साथ एक हो सकते हैं । दिल्ली में रेशम और चमक का बोलबाला है । इस रेशमी नगर में रहने वाले शासक बुनियादी तालीम चलावें और उसमें सफल हों, यह त्रिकाल में भी संभव नहीं है । जनता की दृष्टि कहां है उसको देख कर काम कीजिये । दिल्ली के शासक चाहते हैं कि जनता तो खुरपी चलावे, हल चलावे और हम अपनी मोटर भी अपने हाथ से नहीं चलायें । गांधी जी ने शिक्षा का जो दर्शन सामने रखा है, उसे कार्य रूप में परिणत करने में जो मुशकिलें हैं, जो मुसीबतें हैं, उनको हम नहीं उठावेंगे । बल्कि सारी मुसीबतें तो जनता उठावे और उसके बाद हम सिर्फ मोटरों में जाकर उसको आशीर्वाद दे आवें । यह नहीं होगा और इस तरह काम करने में सफलता भी नहीं मिलेगी ।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

बुनियादी तालीम को योग्यता के साथ वही चला सकता है जिसमें मोटे काम करने की खुद भी कोई उमंग हो और जिसकी आंखों के सामने नगर और कारखाने, महल और मोटर नहीं, बल्कि गांवों के झोपड़े और गरीबों के खेत हों । मेरा खयाल है, भारत का शिक्षा-विभाग बेसिक (basic) शिक्षा के दर्शन को नहीं समझता है क्योंकि दिल्ली की आत्मा उस दर्शन के खिलाफ है । बेसिक शिक्षा की योजना जीवन के दर्शन को बदलने की योजना है, यहां की सरकार को सचमुच गरीबों की सरकार बनाने का उपाय है । जब तक सरकार के ऊंचे ओहदे नेकटाई धारियों के लिये सुरक्षित हैं तब तक बेसिक शिक्षा को आगे बढ़ने में कठिनाई होती रहेगी । इस शिक्षा को आगे बढ़ाना हो तो परिश्रम का मूल्य बढ़ाना होगा, मोटे काम करने वालों को इज्जत देनी होगी । जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि मिनिस्टर (Minister) बनने के लिये, सेक्रेटरी (Secretary) बनने के लिये, जिलाधीश बनने के लिये यह जरूरी नहीं है कि लोग कालेजों में जाकर विदेशी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करें । गांधी जी कहा करते थे कि मैं चाहता हूं कि

[Shri R. D. Sinha Dinkar.]

स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति, किसान का बेटा नही, कोई किसान ही बने। यह तो संयोग की बात है कि आज जो राष्ट्रपति है, वे किसान के बेटे है, मगर अभी वे भी किसान नही है। गांधी जी की कल्पना थी कि हमारे किसान में राष्ट्रपति बनने की योग्यता आनी चाहिये। मगर, यह योग्यता आये कहा से? किसान के लिये तो चारो ओर जहर की दीवार खडी है। इस देश की जनता अंग्रेजी नही जानती है। मगर नेता और शासक अपनी भाषा अंग्रेजी रखे हुये है। उन्हे यह भय जकड़े हुयें है कि जो राज्य महारानी एलिजाबेथ की भाषा में चल रहा है, वह जनता की भाषा मे कैसे चलेगा? नतीजा यह है कि जो अंग्रेजी जाने, जो रेशम का खर्च जुटा सके, वही दिल्ली पहुच सकता है। जनता अंग्रेजी नही जानती, लेकिन प्रार्थना पत्र उसे अंग्रेजी मे देना होगा। विलायती दिमाग को लेकर और अपनी भाषा का अविश्वास करके लोग बेसिक शिक्षा चलाना चाहते है। यह नही होगा। जनता मद्रास की हो या पटने की, अपने राज मे उसे अपनी भाषा मिलनी ही चाहिये। यह देशी शिक्षा का पहला सोपान है।

कहा जाता है कि शिक्षा इसलिये नहीं फैलती कि रुपये की तंगी है। मै इसे नही मानता। मलकानी साहब ने सत्य ही बताया है कि सरकार का इरादा मजबूत नही है। इरादा मजबूत होने पर रास्ते जरूर निकल सकते है। श्रीमन्, आपने सुना होगा कि इधर हाल से इस देश में चीन की बहुत प्रसिद्धि फैल रही है। लोग कहते है कि चीन में जब नये शासक आये तब उनके सामने भी धनाभाव की समस्या थी। मगर, उन्होने अपने आप से सवाल किया कि बी० ए० पास व्यक्ति को एम० ए० बनाना जरूरी है अथवा असंख्य निरक्षरो को साक्षर बनाना। और उन्होने निरक्षर जनता को साक्षर बनाने के काम के सामने कालेजों और यूनिवर्सिटियों को गौण बना दिया। यह व्यावहारिक बात थी। क्या यहां की सरकार कुछ ऐसे कदम नहीं उठा सकती?

भारत सरकार खुद स्कूल नहीं चलाती, स्कूल राज्य सरकारें चलाती है। मगर, शिक्षा पद्धति में पथ, प्रदर्शन की जिम्मेवारी उसी की है। उसे चाहिये कि जगह-जगह पर रिसर्च ब्यूरो (research bureau) कायम करे और इस बात का पता लगाये कि बेसिक शिक्षा असफल क्यो हो रही है। कारणो का पता चले तो उन्हे दूर किया जाना संभव है। यह सुझाव एक बार मैने पहले भी दिया था और तब मुझसे कहा गया कि रिसर्च ब्यूरो को हिदायत भेजी जा चुकी है। लेकिन, बिहार में मुझे पता चला कि ऐसी कोई हिदायत केन्द्र से नही आई है।

मगर रिसर्च ब्यूरो बनाने की बात तो दूर रही, जो लोग बेसिक शिक्षा के चालक है, अभी उन्हे ही इस शिक्षा पर विश्वास नही है। वे आपस मे बैठ कर इस पद्धति का मजाक उडाते है।

बेसिक शिक्षा के मामले मे शिक्षा विभाग के ऊपर देश का विश्वास बहुत कम होता जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी मजाक उड़ायें इससे अच्छा तो यह होता कि जब पंचवर्षीय योजना बन रही थी तब वे सरकार को सुझाव देते कि साहब यह गलती आप क्यों कर रहे है। बुनियादी तालीम अगर मजाक की चीज है तो पंचवर्षीय योजना में उसे श्रेष्ठता का स्थान नही दिया जाना चाहिये था और अगर वह श्रेष्ठ है तो उसका मजाक नही उड़ाना चाहिये। लेकिन शिक्षा विभाग के पास ऐसे लोग नही हैं जो बेसिक योजना को ठीक से समझ सकें। ऐसी हालत मे इस प्रस्ताव का समर्थन मै कैसे करूं?

alone was considered as the greatest *'dan'*, the greatest 'gift' or generosity Every citizen ought to do it A *'grihastha'* had a duty to educate the people Even today, in so many villages in Maharashtra and other places, a boy goes to five houses for his fooding, and takes his meal from them This is not considered to be a matter of shame, this is not begging, it is a matter of right So, it pains me to learn that in this country of ours, education has been made available only to 17 per cent of the people Sir, I am not enamoured of figures or percentages This may be the position in bigger cities And what we look for today is character An uneducated person can have better character possibly—and many a time he has—than an educated person But we cannot save our culture, our civilisation, and go forward and be in the vanguard of the nations of the world, if we keep where we are today Basic education, Sir, I consider, is a possibility, if rightly tried And there again, the difficulty, as rightly pointed out by so many hon Members, is what Gandhiji said, the steel frame of bureaucracy It is they who are responsible for it and who have to put into practice these ideas These things cannot merely be attained by order You can regulate the courts of law, you can administer justice by sections and provisions of law, but you cannot educate a man by a code of education It requires free love between the teacher and the taught Even though, Sir, it is more than 30 years, I still remember at least one of the teachers He was a good man I still feel, after I went to college, to the university, how I happened to forget everybody except one Possibly among the score of them that one man had real love for his pupils In the field of education, Sir, it is those persons only who can achieve success who have got the real belief in the manner and the method and the technique which they are supposed to teach I happen to be a member of the School Board of a big city for a number of years And I can also bear witness to the futility of trying to impose on city children the method of basic education which neither their parents nor their teachers like, but which is imposed on them simply in order to make a show that some expenditure from the Budget is being incurred on them It cannot be done like that Sir, from primary education up to the top the whole system requires to be overhauled and reconstructed Just to give an example, a medical student costs the State Government anything from Rs 800 to Rs 1,000 Is it fair for a poor country like India to spend so much on a selected few who happen to be born as sons of richer parents? And in return what do we get? These people, the M B B S, and those who go to England F R C S and M R C S, refuse to go to the villages because they cannot get their fees They exploit the people in their turn because they have to make up the money that their parents had spent over them in as short a time as possible Their fees would be Rs 7 as against the ordinary doctor charging Rs 2 And in this way we subsidise these richer folk There was a strike by the students when the Government of Bombay raised the fees for medical students When some people came and asked my opinion, I said, "It is most unpatriotic" And here you are spending so much on every student Government is losing so much. What is wrong in asking the richer parents to share the losses that the Government make on the education of their children? To my mind, Sir, the entire scheme is wrong I would, if I had the way, do it this way Just as in the old times, Sir, you used to recruit doctors for the army by paying them stipends, let them be taught at Government expense with the condition that they will have to serve the Government at least for seven to ten years on the prescribed scales and they cannot refuse to go wherever they are asked to go To my mind, most of the money on higher education goes that way There are not enough funds for the foundation and we are still groping in the dark

[Shri S. P. Dave.]

and we do not know where we are. For everything the exchequer says, "We have no money". Sir, reports there have been numerous. Last year there was the report of the University Education Commission. Before that there was the Sergeant Report. Before that there was a report on secondary education. What are we to do with this plethora of material which we do not have the time to read, unless we put them into practice? My appeal to the Government of India is that they should seriously think about it. Enough of conferences and Resolutions. Let us try and make a beginning somewhere with something or declare for all time that basic education, even though it may be good, is not practicable and, therefore, let us hear no more about it. Even that is something. It is time not wasted. We do not undertake the experiment with all the enthusiasm and zeal that it requires. We do not apply our minds properly to it but say there are no results. Therefore, let this be entrusted to the care of those who really believe in it. Let the number of such teachers increase itself gradually in course of time, and that would be the real thing to do. One class of 40 pupils will become in course of time 40 good teachers, and if each one of them turns out 40 pupils, the total number of pupils turned out will be 1600 and so on in the geometric progression. Do not engage the services of anybody who has no faith in basic education. Sir, I am told that this is not an orthodox system of the past, but an ultra-modern scientific method tried in America by Montessori and others. So Mahatma Gandhi and others who had faith in basic education were not trying to revive something of the past, but they were ultra-modernists, if I may say so. Sir, I would, therefore, wholeheartedly support the Resolution and I would once again say, let us revise our calendar. Today we are only 17 per cent. literate. Let us see that there is not a single illiterate person in the whole country in ten years' time. I remember that in the previous census the figure was 8, and we have now progressed from 8 per cent. to 17 per cent.

SHRI C. G. K. REDDY: Good progress.

SHRI S. P. DAVE: But is that considerable progress? The figure has risen because of the death rate, but we should remember that side by side with the death rate, our birth rate also is there. Therefore, we have to make a determined effort if we are to achieve our target over a number of years. In the industrial field, we are happy to find that our production of textiles, sugar, jute and everything else is satisfactory, but in this educational field, in the field of educating men and building up their character, where are we? Far, far away from our target. If we here at the top in the Central Legislature do not think about it, shall we leave it to the poor man? Are we going to take the initiative from him and inspire him to do something which will be really inspiring? We are talking about physical laboratories and research institutes. They are good; I am not against them. They may be helpful to the country, but what is the good of having a few Meghnad Sahas and C. V. Ramans amidst 36 crores of our people who are mostly illiterate? (*Time bell rings*). I would not take more time. I commend this Resolution to the House with the prayer that the hon. the Minister for Education and the Ministry of Education.....

PROF. G. RANGA: *In absentia.*

SHRI S. P. DAVE:.....be pleased to remove the cobwebs of the past, take a new path and blaze a new trail for the future to come.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 1-30 P.M. on Monday.

The Council then adjourned till half past one of the clock on Monday, the 14th December, 1953.